भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
30.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1811 का उत्तर

रेल संरक्षा आयोग द्वारा जांच

1811. श्री यूसुफ पठान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सभी गंभीर दुर्घटनाओं की जांच रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा की जानी अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान गंभीर दुर्घटनाओं के लिए सीआरएस के तहत शुरू की गई जांचों की संख्या का दुर्घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरी की गई जांचों और सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) किसी लंबित जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूरी की गई और सरकार को प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के परिणामों का दुर्घटना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सांविधिक निकाय है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 114 के तहत, रेल संरक्षा आयोग उन रेल दुर्घटनाओं की सांविधिक जांच करता है जिनके परिणामस्वरूप मानव जीवन की हानि हुई हो या गंभीर चोट लगी हो या रेल संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा हो। इसके अतिरिक्त, रेल संरक्षा आयोग किसी भी अन्य दुर्घटना की जाँच करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके बारे में उसका विचार हो कि ऐसी जाँच अपेक्षित हो।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, एक मामले को छोड़कर, रेल संरक्षा आयोग के अंतर्गत सभी जाँचें पूरी हो चुकी हैं और रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं। जाँच रिपोर्टों में रेल संरक्षा आयोग द्वारा सुझाई गई सिफारिशों पर संबंधित रेल प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

******